Prepare IAS
Current Affairs (Oct.7 to Oct.14)

G.S.Paper II & III: International Relations & Indian Economy

** The CRA is generally seen as a competitor to the International Monetary Fund (IMF) and along with BRICS New Development Bank (NDB) is viewed as an example of increasing South-South cooperation.

** Both CRA and NDB were announced as part of BRICS Fortaleza Declaration announced during 6th BRICS summit held in Fortaleza, Brazil in July 2014.

** The initial total committed resources of the CRA will be 100 billion dollars with individual commitments as follows: China ($41 billion), India ($18 billion), Brazil ($18 billion), Russia ($18 billion) and South Africa ($5 billion).

G.S. Paper II: International Organizations

** राष्ट्रमंडल 53 देशों का समूह है, जिसके ज्यादातर सदस्य ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व उपनिवेश हैं।

** पिछले महीने राष्ट्रमंडल मंत्रिस्तरीय कार्रवाई समूह (सीएमएजी) ने राजनीतिक संकट सुलझाने की दिशा में प्रगति नहीं होने पर 'गहरी निराशा' जताते हुए मालदीव को संगठन से निलंबित करने की चेतावनी दी थी।

BRICS Contingent Reserve Arrangement operational:

The Economic times

A crucial economic mechanism to help BRICS member nations - Brazil, Russia, India, China and South Africa - deal *with economic crisis, like balance of payments pressures*, has become operational, said finance minister Arun Jaitley today. The Contingent Reserve Arrangement or CRA was declared operational, after being signed more than a year ago, in 2015.

Mr Jaitley said that central banks of member states are "fully ready to carry out" all transactions in support of other member states. He made the announcement at the annual meeting of the International Monetary Fund and the World Bank.

The CRA was established last year with the aim of providing support through additional liquidity and other means to BRICS countries at a time of economic crisis. It marks an important step in economic cooperation between member countries, and implies a commitment from each member that it will support the other during crisis.

Mr Jaitley also chaired two sessions of the Commonwealth Finance Ministers' meeting - first on the 'Economics of Climate Change and Financing Climate Adaptation and Mitigation' and the second on 'International Taxation - a Commonwealth Conversation Around the Panama Papers'.

मालदीव ने राष्ट्रमंडल छोड़ा

नवभारत टाइम्स

मालदीव ने गुरुवार (13 अक्टूबर) को स्वयं को राष्ट्रमंडल से अलग करते हुए 2012 में राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को सत्ता से हटाए जाने की परिस्थितियों पर और उसके बाद राजनीतिक संकट सुलझाने की दिशा में प्रगति नहीं होने पर द्वीप राष्ट्र को सजा देने के समूह के फैसले को 'अन्यायपूर्ण' बताया। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रमंडल छोड़ने के इस फैसले को 'मुश्किल' और 'अपरिहार्य' बताया।

राष्ट्रमंडल के लिए बेहद महत्वपूर्ण मालदीव ने कहा कि लोकतंत्र को बढ़ावा देने के नाम पर समूह ने देश का उपयोग सिर्फ संगठन की प्रासंगिकता और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में लाभ को बढ़ाने के लिए किया। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, '2012 में मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति (नशीद) के इस्तीफा देने और संविधान में तय प्रक्रिया के तहत सत्ता का हस्तांतरण होने के बाद से ही राष्ट्रमंडल मालदीव के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग कर रहा है।' बयान के अनुसार, 'मालदीव को दंड देने का राष्ट्रमंडल का फैसला अन्यायपूर्ण है, विशेष रूप से तब जब राष्ट्रमंडल की मदद से गठित राष्ट्रीय जांच आयोग (सीओएनआई) ने पाया कि मालदीव में सत्ता का

हस्तांतरण संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हुआ है।'

मालदीव ने कहा कि तभी से सीएमएजी और राष्ट्रमंडल सचिवालय ने मालदीव के साथ 'अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण' व्यवहार किया है। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'राष्ट्रमंडल ने मालदीव के घरेलू राजनीतिक मामलों में सक्रिय भागीदार बनने की बात कही, जो संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रमंडल के चार्टर के सिद्धांतों के खिलाफ है।' उसमें कहा गया है, 'मालदीव आश्वासन देता है कि उसके अंतरराष्ट्रीय संबंध.. द्विपक्षीय और बहुपक्षीय.. दोनों बने रहेंगे।' मालदीव ने कहा कि वह बड़ी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ 1982 में राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ था और उसे लगा था कि यह मंच सदस्य देशों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर समन्वय करेगा, विशेष रूप से संगठन में शामिल छोटे राष्ट्रों के साथ।

G.S.Paper II: Functions & responsibilities of the Union & the States, issues & challenges of federal structure, devolution of powers & finances up to local levels.

** Water is a State subject under VII Schedule of constitution. And so the law will be not binding on States for adoption.

** All basin states have equitable rights over the use of river water provided such use does not violate the right to water for life of any person in the river basin.

** Here equality of rights means not equal but equitable shares in river waters.

Draft water bill proposes 'water for life' for all

Indian Express

A proposed new law on water promises to give every person the right to a minimum amount of "safe water", while making the state "obliged" to "protect" and conserve water.

The draft National Water Framework Bill says every person would be entitled to "water for life" that shall not be denied to anyone on the ground of inability to pay. It defines this "water for life" as that basic requirement that is necessary for the "fundamental right of life of each human being, including drinking, cooking, bathing, sanitation, personal hygiene and related personal and domestic uses". This would also include the additional requirement for women "for their special needs" and the water required by domestic livestock.

The water shortage problem is escalating and country has witnessed acute drought situation in certain parts. In future, such situations may increase backdrop of climate change. Besides, presently in absence of institutional arrangement there are inter-state water disputes because states do not their contributions to a river's catchment area to resolve conflicts.

एकतरफा व्यापार की समस्या

दैनिक जागरण

भारत का चीन के साथ व्यापार एकतरफा हो चला है। हम जितना माल चीन को निर्यात कर रहे हैं उससे लगभग दस गुना वहां से आयात कर रहे हैं। चीनी माल ने चौतरफा तांडव मचा रखा है। पतंग का मांझा, गणेशजी की प्रतिमा, एलईडी बल्ब आदि के बाजार में चीन का बोलबाला है। भारत तथा चीन के बीच सहमति बनी है कि इस एकतरफा व्यापार को संतुलित करने के प्रयास किए जाएंगे, पर हमारा व्यापार घाटा काबू में नहीं आ रहा है। यह काबू में आ भी नहीं सकता, *क्योंकि यह दोनों देशों के मूल आर्थिक मॉडल के अंतर से उत्पन्न हो रहा है।*

आर्थिक मॉडल के इस अंतर को किसी किसान के उदाहरण से समझें। एक किसान को नहर से पूरा पानी नहीं मिलता है, क्योंकि नहर का रखरखाव घटिया है और पानी का रिसाव हो रहा है। उसे बिजली नहीं मिलती है, क्योंकि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा बिजली की बड़े पैमाने पर चोरी की जा रही है। स्पष्ट है कि किसान की उत्पादन लागत ज्यादा और उत्पादन कम है। वह माल को बाजार में बेच नहीं पा रहा है। उसका कारोबार घाटे में चल रहा है, परंतु उसका खेत किसी शहर के नजदीक स्थित है। किसी उद्यमी को उद्योग लगाने के लिए जमीन की जरूरत थी। किसान ने अपनी जमीन का एक हिस्सा एक उद्यमी को बेच दिया। उससे मिले पैसे से फ्लैट स्क्रीन टीवी और महंगी गाड़ी खरीद ली। उसकी खेती घाटे में होने के बावजूद वह ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा है। लगभग ऐसी ही स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था की है। हमारी नहर, बिजली और बुनियादी व्यवस्थाएं खस्ताहाल हैं। जिस प्रकार किसान का कारोबार घाटे में चलने के बाद भी वह कार में ठाठ से घूम रहा है, उसी प्रकार हमारे निर्यात दबाव में रहने के बावजूद हम चीन से गणेशजी की मूर्ति का आयात करके आनंद मना रहे हैं। चीन का मॉडल इससे भिन्न है। चीन के किसान को पानी, बिजली और सड़क उपलब्ध है। उसकी उत्पादन लागत कम आती है। वह चावल और सब्जी को बाजार में बेचकर धन कमा रहा है। कमाई गई रकम से वह शहर में जमीन खरीद रहा है। इससे चीन का मॉडल स्पष्ट होता है। निर्यात से होने वाली आमदनी की वह देश बचत कर रहा है। हमारी बचत दर 28 प्रतिशत की तुलना में चीन की बचत दर लगभग 45 प्रतिशत है। अपनी बचत से वह देश पूरी दुनिया में प्रापर्टी खरीद रहा है। चीन को जितनी रकम विदेशी निवेश से मिलती है उससे अधिक विदेशी निवेश वह अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में कर रहा है। भारत और चीन के आर्थिक विकास के मॉडल में स्पष्ट भिन्नताएं हैं। इन भिन्नताओं को हमें समझना होगा। भारत की बुनियादी व्यवस्था भ्रष्ट और लचर है, जबकि चीन की दुरुस्त है। भारत की अर्थव्यवस्था घाटे में चल रही है। भारत और चीन के बीच व्यापार का असंतुलन इस मूल भिन्नता के कारण है। हम घाटे के बावजूद अपनी जमीन को बेचकर कार का आनंद उठा रहे हैं, जबकि चीन बचत करके दुनिया को खरीद रहा है।

इस विसंगति को छुटपुट कदमों से दूर नहीं किया जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों में व्यवस्था है कि किसी देश द्वारा नीचे दाम पर माल बेचने पर खरीददार देश द्वारा उस माल पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी आरोपित की जा सकती है। **बीते दिनों में भारत द्वारा 344 एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। इनमें से 177 एंटी डंपिंग ड्यूटी चीन से आयात किए जा रहे माल पर लगाई गई है, परंतु इससे चीनी माल का तांडव नहीं रुका है।** तात्पर्य यह कि चीनी माल को दोष देने के स्थान पर उस देश से सीख लेनी चाहिए। अपनी बुनियादी संरचना में व्याप्त अकुशलता एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर अपनी उत्पादन लागत कम करनी चाहिए। ऐसा करने से भारत में बनी गणेशजी की मूर्ति सस्ती पड़ेगी और भारतीय उपभोक्ता चीन में बनी मूर्ति नहीं खरीदेगा। दूसरे, हमें अपनी खपत कम करते हुए अपनी आय का उपयोग दूसरे देशों को खरीदने में करना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने किसी समय नारा दिया था कि देश का हर नागरिक सप्ताह में एक दिन उपवास रखे जिससे देश की खाद्यान्न समस्या का आंशिक हल निकले। इसी प्रकार हमें प्रयास करना चाहिए कि देश का हर नागरिक चीन से आयातित माल की खपत कम करे और बची रकम का एक फंड में निवेश करे, जिससे अमेरिका में संपत्ति खरीदी जा सकें। हमारे निर्यात घाटे की समस्या आंतरिक है। यदि समस्या चीन की थी तो इन देशों के निर्यातों में गिरावट नहीं आनी चाहिए थी। अत: हमें अपने चिंतन को दुरुस्त करना चाहिए। 'मेक इन इंडिया' की छत्रछाया में विदेशी निवेश से मिली रकम का उपयोग आयातों के लिए करने के स्थान पर इसका उपयोग दुनिया में संपत्तियों को खरीदने के लिए करना चाहिए। जाहिर है कि अपनी खराब नीतियों का ठीकरा चीन पर फोड़ने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होने वाला।

G.S.Paper III: Indian Economy & issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development & employment

** हमारे माल की उत्पादन लागत ज्यादा आ रही है। हमारे निर्यात दबाव में हैं, परंतु विदेशी निवेशक भारत में निवेश करना चाहते हैं।

** उन्हें हम अपनी जमीन बेच रहे हैं। विदेशी निवेश से मिलने वाली रकम से हम चीन से गणेशजी की मूर्तियों का आयात कर रहे हैं।

** चीन में उत्पादन लागत कम आती है, क्योंकि बुनियादी ढांचा मजबूत है। चीन के निर्यात अधिक और आयात कम हैं।

** भारत द्वारा विदेशी निवेश से मिली पूंजी का उपयोग चीन के सस्ते माल के आयात को किया जा रहा है, जबकि चीन द्वारा दूसरे देशों में विदेशी निवेश करके दुनिया को खरीदा जा रहा है।

** मई 2016 के पूर्व के 18 माह में दक्षिण अमेरिका, रूस तथा अफ्रीका को होने वाले हमारे निर्यातों में लगभग एक तिहाई की गिरावट आई है।

Govt extends anti-dumping duty on certain Chinese products

(Indian Express)

Revenue department has extended anti-dumping duty on import of certain Chinese products, used in garment, footwear and toys manufacturing, for another five years. The anti-dumping duty on 'narrow woven fabrics hook and loop velcro tapes' will be charged at the rate of USD 1.87 per kilogram. These products are mainly used in garment manufacturing, surgical and orthopedic apparatus, shoes and footwear, luggage/bags, toys, automobile upholstery and various other industrial segments.

The Central Board of Excise and Customs (CBEC) imposed the duty based on recommendations of the Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties (DGAD). The DGAD made the case for continuation of the levy after its second sunset review of the anti-dumping duty in force on the imports.

Anti-Dumping Duty is a trade levy imposed by any government on imported products which have prices less than their fair normal values in their domestic market. Thus, it is protectionist tariff that seeks to stop dumping process where company exports a product at a price lower than price it normally charged in domestic market of importing countries'. Anti-Dumping Duty is imposed under the multilateral World Trade Organisation (WTO) regime and varies from product to product and from country to country.

चीन दक्षिण सागर में बना रहा सबसे छोटा परमाणु रिएक्टर

बीजिंग, प्रेट्र : चीन दुनिया का सबसे छोटा परमाणु रिएक्टर विकसित कर रहा है। इसे वह विवादित दक्षिण चीन सागर (एससीएस) स्थित द्वीपों में से किसी एक में स्थापित कर सकता है। उक्त परमाणु रिएक्टर के जरिये बीजिंग वहां रहने वाले परिवारों को बिजली आपूर्ति करेगा। यह परमाणु संयंत्र फिर से ईंधन भरे बिना दशकों तक चलने में सक्षम है। मंगलवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। अंतराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में हारने के बावजूद चीन इन विवादित द्वीपों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में जुटा है। चीन दावा करता है कि लगभग पूरा दक्षिण चीन सागर उसका है। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व सोवियत संघ की नौसेना ने 1970 के दशक में अपनी परमाणु पनडुब्बियों में कॉम्पैक्ट लेड–कूल्ड थर्मल रिएक्टर का उपयोग किया था। चीन भी उसी नमूने पर काम कर रहा है। इसी कारण पांच वर्षों में पोर्टेबल परमाणु बैटरी पैक विकसित करने के लिए चीनी शोधकर्ता गहनता से जुटे हुए हैं। इससे पहले आधिकारिक मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि चीन जल्द ही अपना पहला तैरता हुआ समुद्री परमाणु ऊर्जा प्लेटफॉर्म बनाने पर काम शुरू करेगा।

एशिया क्षेत्र में दखल न दे अमेरिका : बीजिंग : दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विवादों को लेकर बीजिंग और वाशिंगटन के बीच तनाव बढ़ गया है। इसी क्रम में मंगलवार को चीन ने अमेरिका को एशियाई मामलों में दखल न देने की चेतावनी दी है। बीजिंग में सातवें सालाना शीआंगशान क्षेत्रीय रक्षा फोरम में बोलते हुए चीनी रक्षा मंत्री चांग वांगयुआन ने एशिया के मौजूदा संकट में अमेरिका के हालिया दखल की अपरोक्ष रूप से आलोचना की।

सड़क पर समान अधिकार का सवाल

■ राजेंद्र रवि

बिहार की राजधानी पटना में 25 सितंबर 2016 को 'सड़क पर समता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय' पर बहु-आयामी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पटना के विभिन्न मंचों की ओर से अभी तक के होते रहे आयोजनों से यह अलहदा किस्म की पहल थी। इसका आयोजन दिल्ली के एक समूह 'इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड सस्टेनेबिलिटी' (आइडीएस) ने किया था। कार्यक्रम की शुरुआत 'शहर में गतिशीलता की झलक' के सवाल को दर्शाते हुए एक प्रदर्शनी से की गई। इसमें पथ-पथिकों, साइकिल चालकों और साइकिल रिक्शा से जुड़े भारतीय समाज और सड़क पर इसकी पूर्व में उपस्थिति, वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य की उड़ान को दर्शाया गया था। गांधी की साइकिल चलाते हुए और उनकी पैदल यात्रा की तस्वीरें मुख्य रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थीं; वहीं रिक्शे से जुड़े कई पैनल लगे थे जो उनके इतिहास, वर्तमान और भविष्य की ओर इशारा कर रहे थे। आयोजकों ने विभिन्न देशों की सड़कों पर हो रहे परिवर्तन और बहसों को उन स्थानों के चित्रों के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी। लगभग तीस पैनलों की श्रृंखला में लगाई गई बहुत ही सुसंगठित प्रदर्शनी, करीने से अपनी बात बिहार के अलग-अलग शहरों से आए प्रतिभागियों से कह रही थी। इस प्रदर्शनी की खास बात यह थी कि इसकी हर बात हमारे इतिहास को उकेरती थी और मन को भी।

आइडीएस ने पटना की सड़कों पर चल रहे साइकिल रिक्शे के योगदान और अभी की चुनौतियों पर एक व्यापक अध्ययन किया है। इसकी मुकम्मल रपट भी इस समारोह में जारी की गई। यह रपट पटना शहर के विभिन्न इलाकों के साइकिल रिक्शा चालकों, मिस्त्रियों, मालिकों और सवारियों के साथ इंटरव्यू और सामाजिक सरोकारों से जुड़े समूहों, व्यक्तियों, बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत के आधार पर तैयार की गई है। इस रपट में रिक्शा और सड़क-परिवहन की नीतियों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें आकड़ों का बहुत ही सटीक विश्लेषण किया गया है। कुछ रिक्शा चालकों, मिस्त्रियों और मालिकों की बातें भी कायदे से प्रस्तुत की गई हैं जो उनके योगदान और परेशानियों को दर्शाती हैं।

इस अध्ययन के आधार पर इन्होंने अनुशंसा की है कि ''सभी वाहनों-मोटरवाहनों और गैर-मोटर वाहनों, दोनों को एक संयुक्त परिवहन-व्यवस्था के दायरे में रखते हुए उस पर लोकतांत्रिक ढंग से परिचालन की प्रणाली बनाई जाए और भेदभावपूर्ण रवैए को समाप्त किया जाए। साइकिल रिक्शा से जुड़े तमाम कायदे-कानूनों की समीक्षा और बदलाव आज की स्थानीय और वैश्विक जरूरतों और संदर्भों में की जानी चाहिए, क्योंकि आज विश्व में रिक्शे के प्रति नजरिये में व्यापक बदलाव आ रहा है। सभी चौड़ी सड़कों पर साइकिल रिक्शा लेन और संकरी सड़कों तथा सार्वजनिक परिसरों को गैर-मोटर वाहनों के प्रवेश के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। रिक्शा चालकों के लिए रैनबसेरा, सस्ती दर पर पौष्टिक आहार, मुफ्त स्वास्थ्य जांच और दवा की सुविधा सरकार की ओर से की जानी चाहिए। शहर में सड़कों के ढांचागत विकास और विस्तार में गैर-मोटर वाहनों की अनुकूलता की प्राथमिकता कानूनन अनिवार्य बनाया जाए। 'एकल साइकिल रिक्शा मालिक पद्धति' और 'बहुसंख्यक रिक्शा पद्धति' दोनों को कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए और 'पड़ोसी साइकिल रिक्शा नेटवर्क' योजना बनाई और लागू की जानी चाहिए। साइकिल रिक्शा परिवहन के प्रोत्साहन के लिए रिक्शा निर्माताओं, रिक्शा मालिकों और मिस्त्रियों व चालकों को बैंक लोन, व्यवसाय के लिए भूमि आवंटन तथा विभिन्न करों से छूट मिलनी चाहिए।

आज के समय में साइकिल रिक्शे का संदर्भ बहुत व्यापक हो गया है, इससे न सिर्फ हमारे स्थानीय कारीगरों को रोजगार और बढ़ावा मिलेगा बल्कि इससे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से भी राहत मिलेगी। इसलिए इनकी डिजाइन को समाज के अनुकूल किया जाए। इसे वैज्ञानिक प्रगति का लाभ दिया जाए। इसके लिए जरूरी है कि हमारे राजनीतिज्ञ, योजनाकार, नौकरशाह, वैज्ञानिक, शहरी विकास के नीति नियंता और समाज परिवर्तनकर्मी इस मसले में रुचि लें और पहल करें।''

इस रिपोर्ट का लोकार्पण बिहार के परिवहन मंत्री चंद्रिका राय, पटना के महापौर अफजल इमाम, दिल्ली आइआइटी की परिवहन विशेषज्ञ गीतम तिवारी, अन्विता अरोड़ा, मुंबई से शहरी मामलों के रणनीतिकार राजेंद्र भिसे, बिहार के पूर्व मंत्री रामदेव यादव के सान्निध्य में सामूहिक रूप से किया गया, जिसमें काफी तादाद में रिक्शा समूह से जुड़े लोग भी शामिल थे। इस अध्ययन और समारोह के बारे में आयोजकों ने बताया कि पटना में अध्ययन से पूर्व इन्होंने राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र के चौबीस शहरों में ऐसा ही अध्ययन किया, जिसके आधार पर साइकिल रिक्शा की खातिर एक मुकम्मल नीति बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया। परिणामस्वरूप 2006 में जब केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति बनाई तब उसमें साइकिल रिक्शा, साइकिल और पद-पथिकों के सवाल को भी शामिल किया। उस नीति में साफ-साफ कहा गया है कि सरकार लोगों की गतिशीलता को बढ़ाएगी, न कि मोटरवाहनों को।

पटना शहर ऐतिहासिक शहरों में से एक है। साइकिल रिक्शा यहां की हर सड़क पर विराजमान रहा है और लोगों की जिंदगी में भी। पटना रेलवे स्टेशन के गेट पर पहले रिक्शों का ही साम्राज्य था, लेकिन अब उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया है। आज पटना प्रदूषित शहरों की सूची में अग्रणी है। इसकी एक वजह मोटरवाहनों की बढ़ती संख्या है, जो वायु और ध्वनि प्रदूषण तो बढ़ा ही रही है, सड़क-दुर्घटना और सामाजिक तनाव को भी बढ़ा रही है। रिक्शा प्रदूषण-रहित वाहन है और लगभग आठ दशकों से पटना के शहरी समाज से इसका सरोकार रहा है, पर अब धीरे-धीरे दरकिनार होता जा रहा है। सड़कों से इसके अधिकार छिनते चले जा रहे हैं। सामाजिक-राजनीतिक तौर पर इसके पक्ष में उठती आवाजें बंद हो गई हैं।

लगता है, साइकिल रिक्शे की सड़क से बेदखली के मामले में सारी विचारधाराओं के लोगों के बीच गठजोड़ बन गया है। यही वजह है कि जिन सड़कों पर समता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की गूंज उठा करती थी और ये नारे लगते थे 'सौ में नब्बे शोषित हैं, नब्बे भाग हमारा है', 'कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा', उससे उलट आज वहां की हर धारा का राजनैतिक नेतृत्व यह कहता है कि सड़कों पर कारों को चलने की जगह नहीं है तो रिक्शे को कैसे जगह मिलेगी। वे यह भी कहते हुए गुरेज नहीं करते कि आधुनिकता की दौड़ में रिक्शे के लिए कहां जगह है! इस बात को कुछ दूसरी तरह से परख कर देखें।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, पटना में कारों की संख्या चार प्रतिशत है, मगर यही कारें पटना की सड़कों पर राज करती हैं। शहर के सौ प्रतिशत लोग किसी न किसी हद तक पैदल चलते हैं जिनमें कार वाले लोग भी शामिल हैं। लेकिन पैदल राहगीरों के लिए कहीं भी सुरक्षित चलने के रास्ते नहीं हैं। बड़ी संख्या में नागरिक साइकिल से चलते हैं। सरकार भी साइकिल बांटती है और इसे बढ़ावा देती है! लेकिन वे सब अपनी जान जोखिम में डाल कर सड़क पर चलते हैं। साइकिल रिक्शा आम आदमी से लेकर खास आदमी की सवारी है, लेकिन इसकी हालत बदतर ही होती जा रही है। ऐसे में जो लोग समाज और राजनीति में समता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वे सड़क पर समान अधिकार की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मगर वही चुप हैं तो इसका मतलब क्या लगाया जाए!

गौतम तिवारी ने कहा कि विकसित देशों में एक हजार में नौ सौ नब्बे लोगों के पास कारें हैं और उनकी जिंदगी कारों से आने-जाने में ही गुजर जाती है। शारीरिक श्रम नहीं करने की वजह से वे मोटापा, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग के शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर इन्हें शारीरिक श्रम करने को कहते हैं। ये लोग जिम में जाकर साइकिल चलाते हैं और रैंप पर दौड़ लगाते हैं। क्या हम भी उसी ओर नहीं बढ़ रहे हैं? अगर हमें इससे बचना है तो 'एक्टिव ट्रांसपोर्ट' को अपनाना होगा, जो हमारे समाज में है और हमारी जरूरत भी है, वह है पैदल यात्रा, साइकिलिंग और साइकिल रिक्शा।

आज साइकिल रिक्शा यूरोप और अमेरिका में आ रहा है और हम उसे हटा रहे हैं, यह आधुनिकता नहीं है। अन्विता अरोड़ा ने कहा कि जिस समाज में सबसे कमजोर लोग सुरक्षित नहीं हैं वह समाज तरक्की नहीं कर सकता। जिस सड़क पर एक बूढ़ी औरत और छोटी बच्ची आराम से आ-जा सकती हैं, वही सड़क सबसे आधुनिक है। राजेंद्र भिसे ने बताया कि रिक्शे की कोई जनगणना नहीं होती, तो फिर इसके लिए योजना कैसे बनेगी! योजना के लिए सबसे पहले संख्या जानना जरूरी है ताकि बजट में उसके लिए प्रावधान किया जा सके। परिचर्चा में शामिल रिक्शा समूह के लोगों ने शहर की सड़कों से हो रही रिक्शे की बेदखली और गैरबराबरी का मुद्दा उठाया और कार्यक्रम की सराहना की। बिहार के परिवहन मंत्री चंद्रिका राय ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि इनका हक सुरक्षित रहे। महापौर अफजल इमाम ने कहा कि इनके लिए बनाए गए रैनबसेरों से अवैध कब्जा हटाया जाएगा और आप कोई नीति-मसविदा तैयार करते हैं तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे।

यह आयोजन एक नई दिशा और चिंतन की ओर बढ़ने की एक छोटी पहल है। उम्मीद है कि जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और सड़क पर समता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के सपने को साकार करने में मददगार बनेगी।

पैदल राहगीरों के लिए कहीं भी सुरक्षित चलने के रास्ते नहीं हैं। बड़ी संख्या में लोग साइकिल से चलते हैं, लेकिन अपनी जान जोखिम में डाल कर। साइकिल रिक्शा की हालत बदतर ही होती जा रही है। ऐसे में जो लोग समता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वे सड़क पर समान अधिकार की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा?

जनसत्ता Mon, 10 October 2016
epaper.jansatta.com/c/13820692

Having options is the best option for Indian farmers

The EconomicTimes

Agricultural markets in India are undergoing profound changes. *Direct benefit transfers, reduction in subsidies, liberalisation and integration are increasing uncertainty and expanding the need for risk-shifting strategies.* Options can be a valuable weapon in the farmer's arsenal in the tactical war for survival.

Across the world, the push for adoption comes when agricultural markets shift from government-regulated price stabilisation policies to a free market. A study in South Africa found that after liberalisation, 10 per cent of maize farmers directly participated in derivatives. Younger, less

experienced but better educated farmers, especially those with debt and leased land, were the early adopters.

In the US, 33 per cent farmers use derivatives. In the more protected EU market, that number is between 3 per cent and 10 per cent. India's path towards adoption must begin from a realistic understanding of what options can and cannot do. Agricultural markets are inherently unstable. Because demand and supply of crops is fixed in the short run, prices fluctuate widely within a season and from one year to the next. *The price volatility in pulses — from record highs to below minimum support price — within a few months shows the high variability in farm incomes.* Farmers want protection from this shortterm price risk.The solution is to transfer the risk to someone else while marketing the crop. But the next question for the farmer is one of profitability: how does one transfer risk in a way that doesn't eat into the margins needed to keep the farm running? Compared to mandis or contract farming, commodity exchanges are the biggest market for finding someone to pass on price risk.

Though farmers can use futures contracts for protection against price volatility, they face challenges. *Hedging, by nature, limits profits when prices rise.* The daily demand for margin money affects farm cash flows. Time and effort are needed for initiating the positions, rolling over and liquidation.Options take away these pain points. Aone-time payment of premium gives the right, but not the obligation, to buy or sell a commodity to another party at a specific price on a specified date. So, for example, a chana farmer should be able to buy a put (right to sell) option in October as insurance against prices going down in March, when the harvest arrives. By paying the relatively small premium, he will insure the minimum price. If the market moves up, the premium he paid for the option will be lost.

But he will be able to capitalise on selling chana physically at higher prices. If chana prices are likely to rise, instead of waiting in expectation, the same farmer can sell in the mandi and simultaneously buy a call (right to buy) option to profit from the rise. Options are the next step after crop insurance. Crop insurance only protects farm income against loss of harvest. Options protect farm income from the harvest that is reaped.Except in wheat and rice that have partial protection through government procurement, Indian farmers are buffeted by inefficient physical markets. Therefore, farmer producer companies and cooperatives can be encouraged to use options to manage commercial risk in the production, processing and marketing of agricultural products. Banks can extend credit to purchase price insurance.

Food inflation and food subsidy can be stabilised. Through the ability to use options, processors and merchandisers can pay farmers the best prices for their crops and give consumers lower prices for food. Call options — that give the government the right, but not the obligation, to buy, say, pulses when prices rise — will reduce the need for accumulating physical stocks and add transparency by setting clear rules for government intervention. Potential speculators will get a strong signal to desist from hoarding. Formal price risk management is not for the poorest of the poor. The main clients for such insurance will be commercial-oriented farmers. They may have small farms but they are producing a surplus that they market. They get credit and spend money on inputs.These commercial farmers, too, will need educating. They have to understand that when you pay the premium for an option, you want to lose the money. Exactly like when we want to lose the accident insurance premium instead of wanting to collect it. Another issue is the willingness to pay. Put

option premiums can be expensive exactly at the times when price insurance is most needed: that is, for longer dated periods and when price volatility is high. Options won't reduce price volatility, but they can help manage its fallout.

GS-II: Issue related to social justice

**Talaq-e-bidat is instantaneously granting the divorce just by uttering the word Talaq three times.

Nikah halala is prohibition on remarriage with the divorced husband without consummating marriage with another man.

**Article 13 states that laws that are inconsistent with or in derogation of the fundamental rights are void.

Pursuit of Equality

(The Indian Express)

Article 25 of the Indian Constitution guarantees all citizens the right to practice and profess a religion of their choice. But **can this freedom of religion trump fundamental rights like the right to equality?** In response to a Supreme Court notice on a clutch of petitions challenging triple talaq, nikah halala and polygamy as violating women's right to equality in the name of religion, the Centre has taken a strong position that gender equality and dignity of women are non-negotiable overarching constitutional values and can brook no compromise. This is the modern, secular, democratic and just position.

While many Muslims welcome such movement towards abolishing triple talaq, nikah halala and polygamy, it continues to face strong and vociferous resistance from certain conservative Muslim organisations, whose counterarguments range from sexist to bizarre. AIMPLB for example argues that banning polygamy and triple talaq will mean many women will stay spinsters as they outnumber men (no they don't) and will force husbands to get rid of their wives by murdering them. What undermines the conservatives completely is that *many countries where Islam is the state religion have already banned practices like triple talaq. When religion is not impervious to reform or reinterpretation even in theocratic countries, how can it remain so in a secular democracy?*

There had been concerns that the matter would be muddled by a simultaneous push for a Uniform Civil Code, where the BJP led government would be suspected of baiting Muslims rather than championing women. But the response of the Centre in the Supreme Court has remained focussed on women's constitutional rights to equality. This is the right approach for building momentum to free all citizens from the patriarchal time warp.

प्राइम टाइम इंट्रो : क्या तीन तलाक़ की प्रथा ख़त्म होनी चाहिए?

रवीश कुमार NDTV

जिस दौर में जी रहे हैं उसमें पितृसत्ता को लगातार मिलने वाली चुनौतियां तेज़ होती जा रही हैं. कब कौन सी बहस किस रफ्तार से उठेगी इस पर अब किसी का बस भी नहीं चल सकता. तीन तलाक को समाप्त किये जाने की बहस बेहद रोचक दौर में है. इसका स्वागत होना चाहिए और इस बहाने राजनीतिक पूर्वाग्रहों को स्थापित करने के प्रयासों से सतर्क भी रहना चाहिए. न ही किसी दूसरे भय के आधार पर तीन तलाक का विरोध होना चाहिए. इस टॉपिक पर बहस शुरू नहीं हुई कि फैसला आ जाता है.

मैं उल्टा चाहता हूं. फैसले से पहले हम दोनों पक्षों के बारे में ऐसे बात करें जिससे समाज धर्म और अधिकारों की लड़ाई को समझने में मदद मिले.

उत्तराखंड के काशीपुर की शायरा बानो. फरवरी 2016 में एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि तीन तलाक की प्रथा समाप्त हो. बल्कि इसके साथ साथ हलाला और बहुविवाह भी समाप्त हो जाए. शायरा बानो के साथ साथ जयपुर की आफ़रीन रहमान, हावड़ा की इशरत जहां भी महिलाओं के अधिकार को लेकर मैदान में आ गईं. सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मामलों को एक साथ सुनना शुरू कर दिया. फरवरी से अक्टूबर तक आते आते इस मामले में पक्ष विपक्ष से कई पैरोकार जुड़ गए हैं. भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन भी इस मामले में पक्षकार बन गया. आंदोलन ने 50000 मुस्लिम महिला और पुरुषों के दस्तख़त जुटाए. तीन तलाक की समाप्ति की याचिका पर सुनवाई जैसे जैसे आगे बढ़ी है वैसे वैसे इसे लेकर सार्वजनिक स्पेस में बहस भी बढ़ने लगी है.

जिस तरह से तमाम मुस्लिम संगठनों ने तीन तलाक के हक़ में सक्रियता दिखाई है, उससे लगता है कि मुस्लिम समाज की कोई बेचैनी बाहर आ रही है. समान आचार संहिता अलग मसला है लेकिन इसके सहारे तीन तलाक का समर्थन करना क्या वक्त की मांग को अनदेखा करना है या वाकई उनका इस बात में यकीन है कि तीन तलाक महिलाओं के लिए बेहतर व्यवस्था है. तमाम संस्थाओं, शहरों से लेकर लेकर तमाम दफ्तरों को महिलाओं के हिसाब से कानून बदलने पड़ रहे हैं. क्या मुस्लिम संगठन सिर्फ इस आधार पर इस आवाज़ को अनसुना कर सकते हैं कि तीन तलाक के ख़िलाफ़ तीन चार महिलाएं ही मैदान में हैं.

जमात ए इस्लामी हिन्द ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन तलाक की प्रथा का जो विरोध किया है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के ख़िलाफ़ है. जमात के मुखिया जलालुद्दीन उमरी ने कहा है कि तलाक और बहुविवाह उनके मज़हब का अंतरंग हिस्सा है, इसलिए शरिया कानून का ही पालन होना चाहिए. इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए. दिल्ली में 13 अक्टूबर को दस मुस्लिम संगठनों के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कांफ्रेंस हुई. कहा गया कि सभी प्रमुख मुस्लिम संगठन लॉ कमीशन की उस प्रश्नावली को खारिज करते हैं. लॉ कमिशन ने समान संहिता लागू करने की दिशा में अपनी वेबसाइट पर लोगों से कुछ सवाल पूछे हैं. सारे सवाल हां या ना में पूछे गए हैं और कारण बताने के लिए कुछ जगह भी छोड़ी गई है. भारत सरकार ने कहा है कि तीन तलाक की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने हलफनामे में कहा है कि तीन तलाक होना चाहिए. 70 पेज के हलफनामे का फ्लेविया एग्नेस ने विश्लेषण करते हुए लिखा है कि बोर्ड की कुछ बातें नकाबिले बर्दाश्त हैं तो कुछ बातें सकारात्मक भी हैं. एग्नेस का कहना है कि पहले भी इस मामले में पर्सनल ला बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्वीकार किया है. **भारत की सभी धर्मों की महिलाएं प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत हक मांग सकती हैं.** बोर्ड ने भी यह स्वीकार किया है. फ्लेविया कहती है कि बोर्ड के इस पोज़िशन से यह जो मिथ फैला है कि मुस्लिम औरतें इस कानून के तहत इंसाफ नहीं मांग सकती है, वो दूर हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों से साबित होता है कि बोर्ड अंतिम अथॉरिटी नहीं है.

आज हम सिर्फ तीन तलाक के मसले पर बात करेंगे. वर्ना आप कब तीन तलाक पर बात करते करते समान आचार संहिता पर चले जाएंगे और समान आचार संहिता पर बात करते करते भूल जाएंगे कि तलाक पर बात कर रहे थे. भारत सरकार ने लॉ कमिशन को जिम्मा सौंपा है कि समान आचार संहिता लागू हो. तमाम धार्मिक समुदाय परंपराओं के नाम पर कानून से आगे जाकर छूट लेते रहे हैं. अभी समान आचार संहिता को सिर्फ हिन्दू बनाम मुस्लिम के संदर्भ में भी देखा जा रहा है, लेकिन देखना चाहिए कि यह बहस किसी और दिशा में जाती है या नहीं. क्या समान आचार संहिता बनाते वक्त सभी धर्मों और समाजों की पंरपराओं को एक कानून के तहत लाया जाएगा या जा रहा है.

ग्लोबल वार्मिंग से हिमाचल में बने कई झील बम

शिमला (ब्यूरो)। ग्लोबल वार्मिंग से हिमाचल झील बम की नई परेशानी से घिरता जा रहा है। अभी तक कम होती बर्फबारी से परेशान हिमाचल को अब पिघलते ग्लेशियरों की वजह से बन रहीं नई झीलों से खतरा पैदा हो गया है। स्टेट सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज की ओर से किए गए शोध में यह बात सामने आई है कि पिछले दो सालों में ग्लेशियर के पिघलने से दो सौ से ज्यादा नई झीलें बनी हैं। खास बात यह है कि इनकी न तो निगरानी हो रही है और न ही इनका कोई डाटा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसे में ये झीलें बड़ा खतरा बनती जा रही हैं। रिसर्च की मानें तो चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदी के किनारों पर सबसे ज्यादा ग्लेशियर पिघलने की बात सामने आई है। रिसर्च से जुड़े एसएस रंधावा ने बताया कि 1994 में सतलुज बेसिन के आसपास 38 झीलें थीं। पिछले बीस सालों में यह संख्या बढ़कर 390 पहुंच गई हैं। ग्लेशियरों से बन रही इन झीलों की मॉनीटरिंग की जरूरत बढ़ गई है। उत्तराखंड और नेपाल में कई घटनाओं का उल्लेख करते हुए रंधावा ने कहा कि ये झीलें बढ़ने से प्रदेश में ग्लेशियर पिघलने से झीलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वर्तमान में सिर्फ तिब्बत से सटी स्पीति बेसिन में बने परेचू झील की ही निगरानी हो रही है।

G.S.Paper II *Science & Technology*: developments & their applications & effects in everyday life

** Himalayan region has the largest concentration of glaciers outside the polar caps, as this region is aptly called the "Water Tower of Asia" is the source of the 10 major river systems that provide irrigation, power and drinking water for over 700 million people live in India, Pakistan and Bangladesh– nearly 10% of the world's population.

** According to the UN data, the contribution of snow/glacier melt in annual stream runoff is substantially higher (>40%) in Indus basin as compared to Ganga and Brahmaputra basins (<10%).

G.S.Paper III: Indian Economy & issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development & employment

HIMANSH, India's Remote, High-Altitude Station opened in Himalaya

PIB

As part of the Indian government's initiatives to better study and quantify the Himalayan glacier responses towards the climate change, National Centre for Antarctic and Ocean Research (NCAOR), Goa, under the Ministry of Earth Sciences has established a high altitude research station in Himalaya called HIMANSH (literally meaning, a slice of ice), *situated above 13,500 ft (> 4000 m) at a remote region in Spiti, Himachal Pradesh.*

The station houses many instruments to quantify the glacier melting and its relation to changing climate. Some of the instruments that are available at this research facility include, Automatic Weather Stations for weather monitoring, water level recorder for quantifying the glacier melt, ground penetrating radar to know the thickness of glaciers, geodetic GPS systems to study the glacier movements, snow fork for studying snow thickness, steam drill, snow corer, temperature profilers, as well as various glaciological tools. Further, the researchers would be using this as a base for undertaking surveys using Terrestrial Laser Scanners (TLS) and Unmanned Aerial Vehicles (UAV) that would digitize the glacier motion and snow cover variations with exceptional precision.

Some of the bench mark glaciers that are already being studied under this project include Bada Shigri, Samudra Tapu, Sutri Dhaka, Batal, Gepang Gath and Kunzam. An integrated study using glaciological, geodetic, glacio-hydrological methods will shed light on the glacier response to the changing climate in this region and will also quantify the contribution from glacial melt water to the river discharge in Indus basin. "Himansh" will provide the much needed fillip to the scientific research on Himalayan glaciers and its hydrological contribution.

खुदरा मुद्रास्फीति 13 महीने के निचले स्तर पर, सब्जियां सस्ती

सब्जी, दला-दलहानों और दूध तथा अंडों के सस्ता होने खुदरा मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में घटकर 4.31 प्रतिशत पर आ गई. **यह इसका 13 महीने का न्यूनतम स्तर है.** उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में 5.05 प्रतिशत थी. पिछले साल सितंबर में 4.41 प्रतिशत थी.

इससे पहले, अगस्त 2015 में यह 3.74 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर थी. रिजर्व बैंक प्रमुख नीतिगत दर पर फैसला करते समय खुदरा मुद्रास्फीति को ध्यान में रखता है. उसे खुदरा मुद्रास्फीति को दो प्रतिशत घट-बढ़ की सीमा के साथ 4.0 प्रतिशत के इर्द-गिर्द रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

सरकार द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार सितंबर में सब्जियों के दाम एक साल पहले की तुलना में 7.21 प्रतिशत घटे. अगस्त में सब्जियों के वर्ग में महंगाई दर 1.02 प्रतिशत थी. सब्जियों की तरह दाल-दलहनों, अंडा और दूध एवं उसके उत्पाद खुदरा भाव भी सितंबर में नरम हुए.

मांस तथा मछली की मुद्रास्फीति भी सितंबर में 5.83 प्रतिशत रही जो इससे पिछले महीने के मुकाबले मामूली रूप से कम है. हालांकि फलों की कीमतों में पिछले महीने तेजी आई. कुल मिलाकर उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति पिछले महीने 3.88 प्रतिशत पर आ गई जो अगस्त में 5.91 प्रतिशत थी.

हालांकि ईंधन और बिजली खंड में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति सितंबर महीने में बढ़कर 3.07 प्रतिशत रही जो अगस्त में 2.49 प्रतिशत थी. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार शहरी क्षेत्रों में खुदरा मुद्रास्फीति आलोच्य महीने में 3.64 प्रतिशत रही जो इससे पूर्व महीने में 4.22 प्रतिशत थी. ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर सितंबर महीने में 4.96 प्रतिशत थी जो अगस्त में 5.87 प्रतिशत थी.

मुद्रास्फिति को मुद्रा प्रसार भी कहा जाता है| सामान्यतः मुद्रा प्रसार से आशय सरकार अथवा बैंक द्वारा आवश्यकता से अधिक मात्रा में नोट निर्गमन करने से होता है जिससे मुद्रा की इकाई का मूल्य गिर जाता तथा सामान्य मूल्य स्तर ऊंचा उठ जाता है| इस प्रकार मुद्रा प्रसार की स्थिति में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है जबकि वस्तुओं तथा सेवों की मात्रा उसकी तुलना में कम रहती है| इससे सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है| इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है|

दलहन और चीनी के दाम तय कर सकेगी सरकार दैनिक भास्कर

महंगाईपर अंकुश लगाने के इरादे से सरकार ने माप पद्धति नियमों (मेट्रोलॉजी रूल्स) में बदलाव किया है| इससे असाधारण परिस्थितियों में वह दलहन और चीनी जैसे आवश्यक जिंसों का खुदरा दाम तय कर सकेगी। *मौजूदा व्यवस्था में खुदरा कीमतें मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होती है|* ऐसे में सरकार के पास कीमतों में अचानक हुई वृद्धि पर रोक के लिए अधिक गुंजाइश नहीं बचती।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने पहले ही वैध माप पद्धति (पैकेट बंद जिंस) नियमों, 2011 में संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है। इसमें आवश्यक जिंस का खुदरा मूल्य तय करने का प्रावधान शामिल किया गया है। यह नियम उन आवश्यक जिंसों पर लागू होगा जिन्हें खुला तथा पैकेट बंद दोनों में खुदरा बाजारों में बेचा जाता है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार आवश्यक जिंसों का खुदरा दाम दैनिक आधार पर तय करेगी, अधिकारी ने कहा कि ऐसा नहीं है। **यह सिर्फ असामान्य परिस्थितियों में होगा, जबकि खुदरा कीमतों में सामान्य बढ़ोतरी दिखाई देगी।** फिलहाल अभी तक थोक कारोबारियों तथा आयातकों पर नियंत्रण के उपाय थे, रिटेलरों पर नहीं। इस प्रावधान से सरकार को उपभोक्ताओं के हितों में अग्रसारी कदम उठाने में मदद मिलेगी।

दालों के दाम नियंत्रित करने की कोशिश, अभीकेंद्र सरकार दालों की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, जो जून 2016 के दौरान खुदरा बाजार में 200 रु. किलो तक पहुंच गई थी। इसकी वजह सूखा पड़ने की वजह से देश में दलहन का उत्पादन कम होना है। दालों की कीमतों में अप्रत्याशित तेजी की वजह से एनडीए सरकार को कई कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा है। इन कदमों में दलहन का आयात और न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करना शामिल है। ताकि घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाकर दालों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। महंगेप्याज का राजनीतिक असर : काबिलेगौरहै कि प्याज की कीमतों में तेजी की वजह से सरकारों के भविष्य पर असर पड़ता है। वर्ष 1998 में प्याज महंगा होने से दिल्ली में बीजेपी सरकार को चुनाव में हार मिली थी और कांग्रेस सत्ता में गई थी।

Prepare IAS
Current Affairs (Oct.7 to Oct.14)
RBI to be divested of debt management role in 2 years

(The Hindu Business Line)

The Centre has finally made up its mind on setting up an independent agency to mange its debt after years of discussions with the Reserve Bank of India. As a precursor, the Finance Ministry will soon set up the Public Debt Management Cell (PDMC) in the Budget Division.

"This interim arrangement will allow separation of debt management functions from RBI to the Public Debt Management Agency (PDMA) in a gradual and seamless manner, without causing market disruptions," said the Ministry, adding that the cell will be converted to a statutory authority in about two years' time.

According to the Finance Ministry, the PDMC will at present only have advisory functions to avoid "any conflict" with the statutory powers of the RBI. To start with, it would plan the borrowings of the Centre, manage the Central government liabilities and monitor the cash balances.

It would also develop an integrated debt database system as a centralised data base for all liabilities of the government on a near real time basis.

To be initially located in the RBI's Delhi office, the PDMC will also advise government on matters related to investment, capital market operations and interest rates on small savings as well as undertake requisite preparatory work for PDMA.

The PDMC would be staffed with 15 "experienced" debt managers from the Budget Division, RBI, middle office and other units and would be under the overall supervision of the Joint Secretary (Budget), Department of Economic Affairs.

"The transition process from PDMC to PDMA would be implemented by a joint implementation committee (JIC)," said the Ministry. The JIC would in turn be supervised by the monitoring group on cash and debt management that would be co-chaired by Economic Affairs Secretary and RBI Deputy Governor.

** Former Finance Minister Pranab Mukherjee had first announced the setting up of PDMA in Budget 2011-12, which was later also backed by the Financial Sector Legislative Reforms Commission in its report in 2013.

** The Joint Secretary (Budget), Department of Economic Affairs of the Finance Ministry will be the overall in-charge of the PDMC.

** The setting up of the PDMA has been a top priority for the government and a pending financial sector reform, as it would help divest the RBI of its dual and often conflicting roles as the banker and manager of the Centre's borrowing.

चीन दक्षिण सागर में बना रहा सबसे छोटा परमाणु रिएक्टर

बीजिंग, प्रेट्र : चीन दुनिया का सबसे छोटा परमाणु रिएक्टर विकसित कर रहा है। इसे वह विवादित दक्षिण चीन सागर (एससीएस) स्थित द्वीपों में से किसी एक में स्थापित कर सकता है। उक्त परमाणु रिएक्टर के जरिये बीजिंग वहां रहने वाले परिवारों को बिजली आपूर्ति करेगा। यह परमाणु संयंत्र फिर से ईंधन भरे बिना दशकों तक चलने में सक्षम है। मंगलवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। अंतराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में हारने के बावजूद चीन इन विवादित द्वीपों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में जुटा है। चीन दावा करता है कि लगभग पूरा दक्षिण चीन सागर उसका है। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व सोवियत संघ की नौसेना ने 1970 के दशक में अपनी परमाणु पनडुब्बियों में कॉम्पैक्ट लेड-कूल्ड थर्मल रिएक्टर का उपयोग किया था। चीन भी उसी नमूने पर काम कर रहा है। इसी कारण पांच वर्षों में पोर्टेबल परमाणु बैटरी पैक विकसित करने के लिए चीनी शोधकर्ता गहनता से जुटे हुए हैं। इससे पहले आधिकारिक मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि चीन जल्द ही अपना पहला तैरता हुआ समुद्री परमाणु ऊर्जा प्लेटफॉर्म बनाने पर काम शुरू करेगा।

एशिया क्षेत्र में दखल न दे अमेरिका : बीजिंग : दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विवादों को लेकर बीजिंग और वाशिंगटन के बीच तनाव बढ़ गया है। इसी क्रम में मंगलवार को चीन ने अमेरिका को एशियाई मामलों में दखल न देने की चेतावनी दी है। बीजिंग में सातवें सालाना शीआंगशान क्षेत्रीय रक्षा फोरम में बोलते हुए चीनी रक्षा मंत्री चांग वांगयुआन ने एशिया के मौजूदा संकट में अमेरिका के हालिया दखल की अपरोक्ष रूप से आलोचना की।

ब्रिक्स सम्मेलन | कल से गोवा में शुरू हो रही है शिखर वार्ता, पाक को अलग-थलग करेगा भारत

भारत रूस से खरीदेगा 200 हेलीकॉप्टर और 5 मिसाइलें, 40 हजार करोड़ रु. के होंगे रक्षा सौदे

} भारत में ही बनेंगे कामोव केए 226 टी हेलीकाप्टर, 40 रूस से आएंगेः रूसी मीडिया

एजेंसी | नई दिल्ली/मॉस्को

इस बार ब्रिक्स सम्मेलन गोवा में हो रहा है। यहां 15 और 16 अक्टूबर को ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स की प्रगति पर चर्चा करेंगे। आतंकवाद पर मुख्य फोकस होगा। रूसी मीडिया के मुताबिक इस बैठक से इतर रूस और भारत के बीच 6 बिलियन डॉलर (करीब 40 हजार करोड़ रुपए) के रक्षा सौदे होंगे। इसमें 200 'कामोव केए-226 टी चॉपर और पांच एस-400 मिसाइलें शामिल हैं। खास बात यह है कि समझौते के तहत कामोव हेलीकॉप्टर भारत में ही बनेंगे। फर्स्ट डिलीवरी के लिए 40 हेलीकॉप्टर रूस से आएंगे। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे के समय इस पर सहमति बनी थी। अगर सौदा तय हो जाता है तो इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया को बड़ा बूस्ट मिल सकता है।

रूस के रोसटेक कोऑपरेशन ने कहा है, वह भारत में 'कामोव केए 226 टी' हेलीकॉप्टर की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट लगाएगा। इसके तहत हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ ज्वाइंट वेंचर किया गया है। कोऑपरेशन के तहत 700 से ज्यादा रूसी फर्म हैं। ये सभी कंपनियां रक्षा और तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी हुई है।

कामोव चॉपर व एस-400 मिसाइल- वो सबकुछ, जो आप जानना चाहते हैं...

- यह 8.6 मीटर लंबा, 3.2 मीटर चौड़ा और 4.1 मीटर ऊंचा है।
- छोटा होने से सीमित जगह में लैंड या टेक ऑफ की क्षमता।
- हेलीकॉप्टर में सात पैराट्रूपर की जगह है। ये 3500 किग्रा का सामान ले जा सकते हैं।

33 हजार करोड़ में 5 एस-400 मिसाइल खरीदेगा, 36 मिसाइलों को एक साथ गिरा देने की क्षमता

पांच एस-400 मिसाइल के सौदे पर भी बात हो सकती है। यह सौदा 5 बिलियन डॉलर यानी 33 हजार करोड़ में होने की संभावना है। इस डिफेंस सिस्टम में 400 किमी दूर से आ रहे टारगेट को ट्रैक करने की क्षमता है। एक वक्त में 36 मिसाइलों को टारगेट कर सकता है।

ये मिसाइलें एक तरह से मिसाइल शील्ड का भी काम करेंगी, जो पाकिस्तान या चीन की परमाणु शक्ति संपन्न बैलेस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा प्रदान करेंगी। अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट एफ-35 को गिराने की भी क्षमता है। सौदा होता है तो चीन के बाद इस सिस्टम को खरीदने वाला भारत दूसरा देश होगा।

चीन से नाराजगी जताएंगे मोदी

ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ही पीएम मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होनी है। इसमें मसूद अजहर जैसे आतंकी के खिलाफ कार्रवाई और एनएसजी में भारत की सदस्यता का मामला भी उठा सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलेंगे। जिसमें रूस के साथ कुछ समय पहले रिश्तों में आई खटास को मिटाने की कोशिश होगी। उड़ी हमले के बाद रूस ने पाकिस्तान में सैन्य अभ्यास किया है। भारत अपने राजदूत के माध्यम से मास्को में गहरी नाराजगी जता चुका है।

दुनिया की 22% जीडीपी ब्रिक्स देशों के पास

दुनिया की 53% आबादी ब्रिक्स के इन देशों की जीडीपी करीब 160 खरब है। यानी दुनिया की 21 फीसदी। दुनिया की 53 फीसदी आबादी रहती है।

यूरोपीय समीकरण चुनौती आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा, अमेरिकी चुनाव व यूरोप में नए सियासी घटनाक्रम से ब्रिक्स देशों के सामने जोखिम की संभावना बढ़ी है।

5.1% रहेगी विकास दर ब्रिक्स देशों की वृद्धि चालू वित्त वर्ष में 5.1 प्रतिशत रहेगी। जबकि वैश्विक स्तर पर 3.2 प्रतिशत वृद्धि के अनुमान से अधिक है।

भास्कर एक्सपर्ट

पाक प्रायोजित आतंक पर भारत को देना होगा स्पष्ट संदेश

रहीस सिंह, विदेश मामलों के विशेषज्ञ

- **ब्रिक्स में भारत की कितनी अहमियत?**

आबादी और इकोनॉमी के लिहाज से भारत इस ग्रुप का दूसरा सबसे अहम सदस्य है। इस वक्त रूस और ब्राजील आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका और चीन की रफ्तार स्थिर है। इस नकारात्मक माहौल में भारत की जीडीपी 7.6 फीसदी से बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही भारत में सबसे ज्यादा व्यापार की संभावना है। भारत के बिना ब्रिक्स की कल्पना नहीं की जा सकती है।

- **भारत की तरफ से अहम एजेंडे क्या होंगे?**

भारत का खासा जोर पाक प्रायोजित आतंकवाद पर होगा। भारत को सीमा पार के आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों सदस्यों को सीधे बयान पर राजी करना होगा। हालांकि जैश ए मोहम्मद को आतंकी घोषित करने के भारत के प्रयास को चीन ने झटका दिया है। इस पर भारत को स्पष्ट रूप से बात करनी होगी। सीधे पाकिस्तान का नाम लेना होगा। चीन और रूस ने उइघर और चेचेन आतंकी पर कार्रवाई करने के लिए इस तरह के प्लेटफार्म का इस्तेमाल किया था। जरूरी है कि ब्रिक्स देश आतंक पर स्पष्ट नीति रखें।

- **रूस-भारत के बीच दूरी क्यों दिख रही है?**

यह सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत का अमेरिका और यूरोप की ओर हाथ बढ़ाने की कोशिश से ब्रिक्स का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। इसके चलते रूस को भी लग रहा कि सोवियत संघ से चल दोनों देशों के रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े नहीं है। इन्हें बचाया जा सकता है।

G.S. Paper I: Indian Culture, Salient aspects of Art Forms, Literature & Architecture from ancient to modern times

** Harikatha is a traditional art of story-telling,poetry, music, drama, dance, and philosophy in South India especially in villages of Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu.

** Any Hindu religious theme can be the subject for it.

An effort to revive Harikatha

The Hindu

Harikatha, a form of Hindu religious discourse, is catching up with the younger generation too, thanks to the patronage from various cultural organisations including 'Mitra Samskritika Samiti'

Harikatha, which originated from Ajjada village of Srikakulam, has become popular in other languages too. At its peak, Harikatha was a popular medium of entertainment, which helped transmit cultural, educational and religious values to the masses.

Adibhatla Narayanadas, popularly known as Harikatha pithamaha, continued to be the source of inspiration for many artistes. And, it was proved again with the wonderful response for the recently concluded 'Harikatha saptaham' in Srikakulam.

"The main aim of Harikatha is to instil truth and righteousness in the minds of people and sow the seeds of devotion in them. That is why we have organised 'Harikatha saptaham' in Srikakulm. Many youngsters too attended the programme," says Ippili Shankara Sarma, president of Mitra Samskritika Samiti and chief preist of Arasavilli Sri Suryanarayana Swamy temple.

G.S. Paper II: Pressure groups & formal/informal associations & their role in the polity

कला की सीमाएं नहीं होतीं, लेकिन देश की होती हैं

दैनिक जागरण

इस समय देश में एक नई बहस चल पड़ी है कि कला की सीमाएं होती हैं अथवा नहीं? यदि कोई देश कुछ गलत करता है या गलत का समर्थन करता है तो उस देश के कलाकारों को अन्य स्थानों पर काम करने का अधिकार है अथवा नहीं? एक कलाकार का कला के प्रति समर्पण का पैमाना क्या होना चाहिए?

इस पूरी बहस में मेरा स्पष्ट मत है कि *कला की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन इसके साथ-साथ एक शाश्वत सत्य यह भी है कि एक कलाकार की कला के प्रशंसक भी बिना किसी राजनीतिक सीमा के होते हैं। वे प्रशंसक उस कलाकार में स्वयं को खोजने लगते हैं। वे उस कलाकार के रोने पर दुखी होते हैं और उसी कलाकार के हंसने पर खुश होते हैं। जब वह कलाकार अपने असल जीवन में हॉस्पिटल में ऐडमिट हो जाता है तो वे प्रशंसक अपना खाना छोड़कर भगवान के मंदिर में घंटों उसकी सलामती की दुआएं मांगते हैं।*

धूप नामक फिल्म में जब कोई कलाकार एक शहीद के पिता का किरदार निभाता है तो दर्शक के मन में उस कलाकार की छवि वैसी ही बन जाती है जैसा वह पर्दे पर दिखता

है। जब कोई कलाकार पर्दे पर गर्व नामक फिल्म में एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाता है तो पुलिस में जाने की तैयारी कर रहा नौजवान उसी आभासीय किरदार को प्रेरणा मान लेता है। लेकिन समस्या यह है कि वह नौजवान दर्शक उस कलाकार की कला का नहीं बल्कि उस व्यक्ति विशेष का प्रशंसक बन जाता है।एक कलाकार से अपेक्षा की जाती है कि उसमें मानवीय भावना का स्तर आम जनमानस से अधिक होगा क्योंकि उसने पर्दे पर कई किरदार जिए होते हैं। उसने एक फौजी का, एक पुलिसकर्मी का, एक एक आम आदमी तक का किरदार जिया होता है। हमने तो यही सुना है कि कोई अच्छा अभिनय तभी कर पाता है जब वह अपने आभासीय किरदार में पूरी तरह से उतर जाए। इसी आधार पर हम यह अपेक्षा करते हैं कि एक शहीद के पिता का दर्द, एक आम आदमी का दर्द, एक सैनिक की परिवार से दूर रहने की तड़प, सब कुछ वह हमसे बेहतर तरीके से महसूस कर सकता है। और इसी आधार पर हम यह भी अपेक्षा करते हैं कि जब किसी आतंकी हमले में देश का कोई बेटा शहीद होता है तो उसके पिता की तरह तो नहीं लेकिन हमसे बेहतर तरीके से एक कलाकार उस परिवार के दर्द को महसूस कर सकता है। वह सही मायने में कला का पुजारी तभी माना जाएगा जब वह सभी सीमाओं को तोड़कर प्रत्येक अमानवीय घटना की निंदा करने की क्षमता रखता हो।

निश्चित ही कला की कोई सीमाएं नहीं होतीं लेकिन दुर्भाग्य से देश की सीमाएं होती हैं। ए*क कलाकार की प्राथमिक पहचान उसका देश ही होता है। और यदि कोई ऐसा है जो कला को सच में अपने देश से पहले मानता हो तो उसे उस जगह पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना चहिए, जहां उसे मोहब्बत मिल रही हो, जहां उसकी कला का सम्मान होता हो। और ऐसी जगह पर उसे वहां के कानून के मुताबिक सम्मानपूर्वक रहना चाहिए।* भारत के वे लोग जो मेरी तरह ही इस बात को मानते हैं कि हमारे लिए, हमारी खुशी तथा शांति के लिए अपने घर से दूर रहकर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले हमारे शहीद का बलिदान, कला से भी बड़ा है, वे लोग एक बात को कभी मन में ना आने दें कि 'राष्ट्र सर्वोपरि' के सिद्धान्त पर सिर्फ 'हिंदू' ही चल रहे हैं। उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि अनुपम खेर और नाना पाटेकर के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी आपकी लड़ाई उनके बीच लड़ रहे हैं।

यही सलमान खान कुछ महीने पहले जब मोदी के साथ पतंग उड़ा रहे थे तो बड़े राष्ट्रवादी थे, बजरंगी भाईजान लाए तो कहा कि अरे देखो मुसलमान होकर 'बजरंगी' नाम रखा। सलमान, शाहरुख़ या ओम पूरी को एक झटके में राष्ट्रद्रोही करार देना पूरी तरह से गलत है । लेकिन उससे हम यह अपेक्षा तो करते ही हैं की जब इस देश के 18 बेटों की हत्या हो तोह वह कलाकार इस अमानवीय कुकृत्य की खुले मन से निंदा न करे ।

Automation Monster Coming for Our Jobs **The Economic Times**

Would advances in robotics, materials, artificial intelligence, ubiquitous high-speed networks, driverless vehicles and solar energy have completely transformed the economic landscape and rendered jobs scarce? Scary though the eventuality is, it cannot be dismissed outright. Planners lack the wisdom to divine the future and plan for it.

**According to World Bank research, automation imperils 69 per cent of jobs in India. By 2025, 70 per cent of the country's population would be of working age.

What can be done is to prepare India's biggest strength, its human capital, to become creative and productive in unforeseen circumstances and to create the requisite social and physical infrastructure. Investment in social infrastructure — education, health, skills —must go hand in hand with investment in physical infrastructure. Past technological disruptions conclusively demonstrate that education is the key determinant and predictor of economic growth. Prioritising education requires an exponential increase in public spending on education but that alone is not enough. **There is need for a radical change in the approach to learning, and the focus must be on outcomes.** Critical thinking and challenging of received verities lay the ground for innovation. But a hierarchical society with highly skewed

distribution of social power and wealth militate against a questioning attitude across society. Hyper-nationalism and majoritarianism have a similar effect.

Poverty, malnutrition and dysfunctional schools and public healthcare reinforce one another and the process of stunting minds and bodies. Stunted people are more likely to become victims of rapid social change than to ride it. The need is for inclusive and sustained growth.

Cabinet approves revision of ethanol price for supply to Public Sector Oil Marketing Companies

Business Standard

G.S.Paper III: **Storage, transport & marketing of agricultural produce & issues & related constraints**

The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved the mechanism for revision of ethanol price for supply to Public Sector Oil Marketing Companies (OMCs) to carry out the Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme in the following manner:

i. For the next sugar season 2016-17 during ethanol supply period from 1st December, 2016 to 30th November, 2017, the administered price of ethanol for the EBP Programme will be Rs.39/- per litre.

ii. Additionally, charges will be paid to the ethanol suppliers as per actuals in case of Excise Duty and VAT/GST and transportation charges as decided by OMCs.

iii. If the need arises to increase/reduce the retail selling price of Petrol by Public Sector OMCs, then such increase/reduction would proportionately factor in the requirement of maintaining the fixed cost of purchase of ethanol during the ethanol supply year.

iv. The prices of ethanol will be reviewed and suitably revised by Government at any time during the ethanol supply period that is from 1st December, 2016 to 30th November, 2017 depending upon the prevailing economic situation and other relevant factors.

The revision in ethanol prices will facilitate the continued policy of the Government in providing price stability and remunerative prices for ethanol suppliers.

** Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme was launched by the Government in 2003 which has been extended to the Notified 21 States and 4 Union Territories to promote the use of alternative and environment friendly fuels. This intervention also sought to reduce import dependency for energy requirements.

** Ethanol is biofuel derived from Sugarcane molasses (by-product in the conversion of sugarcane to sugar), corn, sorghum etc.

India to light up IEA's global LED programme The Hindu

G.S.Paper III: *Infrastructure*: Energy, Ports, Roads, Airports, Railways etc.

India, through its company Energy Efficiency Services Limited (EESL), has performed exceedingly well in terms of vastly improving access to LED lighting while reducing their cost drastically, the International Energy Agency said.

"The LED programme by EESL has been so successful that IEA is partnering with it to take the programme global," Paul Simons, Deputy Executive Director at the IEA said while speaking at the World Sustainable Development Summit. "In particular, we would **like to try this model out in Indonesia.** We believe this is a best practice that must be shared."

The price at which EESL has been purchasing LED lights to distribute under the government's Unnat Jyoti **by Affordable LEDs for All (Ujala) scheme** has been consistently falling over the last couple of years. The company purchased LEDs at Rs.310 per piece in 2014, and the price fell to Rs.55 as of March 2016.

Along with this, production has also been ramped up to about four crore per month from the 10 lakh a month that were produced two years ago. LED lights consumes 80 per cent less electricity than incandescent bulbs.

"The 175 GW of renewable energy capacity target by 2022 will not be a problem for India," Upendra Tripathy, Secretary in the Ministry of New and Renewable Energy, said while also speaking at the event.

** Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All (UJALA) scheme UJALA scheme is LED-based Domestic Efficient Lighting Programme (DELP) that aims to promote efficient lighting, reducing energy consumption and energy savings. It was launched as National LED programme by Prime Minister Narendra Modi in January 2015.

**. It was renamed UJALA in March 2016. Under it, every grid-connected consumer having a metered connection from their respective Electricity Distribution Company will get the LED bulbs at subsidized rates.

Indo-Pak. border will be sealed by 2018

The Hindu

G.S.Paper III: Role of external state & non-state actors in creating challenges to internal security

Amid rising tensions between India and Pakistan following the surgical strikes across the Line of Control, Union Home Minister Rajnath Singh on Friday said **the entire stretch of 3,323-km-long border between the two countries would be "completely sealed" by December 2018,** for which a time-bound action plan would be formulated.

Speaking to reporters after holding a security review meeting in Jaisalmer, Mr. Singh said the procedure for sealing the international border would be developed in a planned manner, with a mechanism in place for its periodic monitoring at multiple levels in the defence establishment as well as the governments of

the four border States.

The Home Minister was on a two-day visit to the border areas of Rajasthan, where he interacted with the Border Security Force (BSF) officers and civil administration to review defence preparedness following the attack in the Army camp in Uri on September 18 and the subsequent surgical strikes on terror launch pads. Minister of State for Home Affairs Kiren Rijiju accompanied him.

"The project will be periodically monitored by Home Secretary at the Central level, BSF from the security forces' perspective and Chief Secretaries at the State level," said Mr. Singh, adding that the government would apply technological solutions for sealing the border in difficult terrains.

India-Pakistan share 3,323-km-long border which is termed as International Border. Border between both countries was created based upon the Radcliffe line in 1947. 4 states share this international border with Pakistan. Of this 1,225 km falls in Jammu and Kashmir (including Line of Control), 1,037 km in Rajasthan, 553 km in Punjab and 508 km in Gujarat.

Mr. Singh said a border security grid would also be formed, with guidelines to be framed with suggestions from all stakeholders in the border areas. The concept would be developed and a notification issued for it after getting suggestions from the Chief Ministers, Home Secretaries and Directors-General of Police, he added.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ताजा लिस्ट में पाकिस्तान को बताया दुनिया का चौथा सबसे खतरनाक देश

जनसत्ता ऑनलाइन

भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम विश्व के असुरक्षित देशों में चौथे नंबर पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रेवल एंड टूरिज्म की रिपोर्ट में विश्व के सुरक्षित और असुरक्षित देशों के बारे में बताया गया है। ***असुरक्षित देशों की लिस्ट में नाइजीरिया का नाम सबसे ऊपर है। इसके बाद कोलंबिया, यमन, पाकिस्तान और वेनेजुएला का नाम आया है।*** इनके अलावा मिश्र, ग्वाटमाल, अल साल्वाडोर, थाईलैंड, केन्या, लेबनान, इंडिया, फिलीपिंस और जमैक देश भी शामिल हैं। वहीं भारत इस लिस्ट में 13वें नंबर पर है। सुरक्षित देशों की लिस्ट में फिनलैंड सबसे ऊपर है। इसके बाद कतर, संयुक्त अरब अमीरात, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लक्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ओमान और पुर्तगाल हैं। रिपोर्ट में ज्यादात्तर सुरक्षित देश यूरोप के हैं। वहीं *अरसुरक्षित देशों की लिस्ट में ज्यादात्तर लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और मिडल ईस्ट के देश हैं।*

पाकिस्तान को आतंकवाद पर काबू पाने के लिए कई बार चेताया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी पाकिस्तान को कई बार आतंक को लेकर चेताया है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कोशिश की है, ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग-थलग करने की कोशिश की है।

बता दें, नवबंर महीने में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली सार्क सम्मेलन की बैठक को कैंसिल कर दिया गया। सार्क देशों में नेपाल, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ने सार्क सम्मेलन की बैठक में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। सार्क देशों ने कहा था कि इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन लायक स्थिति नहीं है। भारत ने सबसे पहले इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने से मना किया था। इसके बाद बाकी देश भारत के साथ आ गए थे। इन देशों ने भी सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने से साफ मना कर दिया था।

Prepare IAS
Current Affairs (Oct.7 to Oct.14)
स्पेक्ट्रम नीलामी से सबक

बिज़नस स्टैण्डर्ड

हाल ही में संपन्न स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया के लिए आप चाहे जिस पैमाने का इस्तेमाल करें, हकीकत तो यही है कि यह बुरी तरह नाकाम रही है। नीलामी के पांच दिनों में से किसी भी दिन बोली लगाने का काम तेजी नहीं पकड़ सका जिसका नतीजा यह हुआ कि केवल 40 फीसदी स्पेक्ट्रम की ही बिक्री हो पाई। *सरकार ने नीलामी के जरिये 2355 मेगाहट्र्ज का स्पेक्ट्रम बेचने का लक्ष्य रखा था लेकिन 965 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम के ही खरीदार सामने आए।* देश के कुल 11 दूरसंचार ऑपरेटरों में से केवल सात ऑपरेटर ही इस प्रक्रिया में शामिल हुए।
वोडाफोन ने भी थोड़ी ज्यादा सक्रियता इसलिए दिखाई क्योंकि उसकी मूल कंपनी ने 47 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डाली थी। लगभग सभी ऑपरेटर बोली लगाने में चुनिंदा रवैया ही अपनाए रहे। उनका जोर इस बात पर था कि उनके हिस्से में केवल उतना ही स्पेक्ट्रम आए जो 4जी सेवा शुरू करने के लिए जरूरी हो। यही वजह है कि *4 जी सेवाओं के लिए मुफीद माने जाने वाले 1800 मेगाहट्र्ज, 2300 मेगाहट्र्ज और 2500 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की ही मांग ज्यादा दिखी।* ऐसे में सरकार अपने राजस्व लक्ष्य से बहुत पीछे रह गई। समूचे स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए *सरकार ने 5.66 लाख करोड़ रुपये का आधार मूल्य तय किया था लेकिन उसे बोली के तौर पर केवल 65,789 करोड़ रुपये ही मिले जो लक्ष्य का महज 11.5 फीसदी है।*

यह रकम 2015 में हुई पिछली नीलामी में मिली 1.1 लाख करोड़ रुपये की रकम से भी करीब आधी है। गलती कहां पर हुई? इस सुस्त प्रतिक्रिया के लिए कई कारण गिनाये जा रहे हैं लेकिन एक अहम पहलू यह है कि सरकार ने स्पेक्ट्रम का आरक्षित मूल्य काफी ऊंचा रखा। शायद सरकार को यह अंदेशा था कि कम आरक्षित मूल्य रखने को कहीं दूरसंचार उद्योग के लिए एक कृपा के रूप में न देखा जाए जो आगे चलकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के ध्यान का भी सबब बने। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र पिछले कुछ समय से संघर्ष कर रहा है। इस उद्योग पर पहले ही 3.8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज चढ़ा हुआ है जो कि उसके सालाना राजस्व से भी अधिक है। उपभोक्ताओं की संख्या के 95 करोड़ से भी पार पहुंचने के बाद विकास की रफ्तार काफी धीमी हो गई है जबकि प्रतिस्पद्र्धा काफी बढ़ गई है। रिलायंस जियो के प्रवेश ने तो उनके लिए हालात को और भी मुश्किल बना दिया है। अब ऑपरेटरों का ध्यान वॉयस कॉल के बजाय डेटा सेवाओं पर केंद्रित हो गया है। इससे पहले से ही भारी कर्ज में डूबे ऑपरेटरों को कीमत के मोर्चे पर भी जंग के लिए तैयार होना पड़ा है।

असलियत तो यह है कि आज किसी भी ऑपरेटर के पास नकदी नहीं है। सरकार ने कुछ बैंड्स के लिए अधिक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखकर हालात को और भी खराब बना दिया। दरअसल सालाना 2.5 लाख करोड़ रुपये के राजस्व वाले उद्योग के लिए नीलामी में दोगुने से भी अधिक का लक्ष्य रखना तर्कसंगत नहीं है। इस तरह की नाकाम नीलामी का असर भी देखने को मिलेगा। बजट में घोषित 56 हजार करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य के विपरीत सरकार को स्पेक्ट्रम नीलामी से इस वित्त वर्ष में केवल 32 हजार करोड़ रुपये ही मिलेंगे। ऊंचे आरक्षित मूल्य के चलते 700 और 900 मेगाहट्र्ज बैंड्स के लिए कोई बोली ही नहीं मिल पाई। ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा सेवाओं के विस्तार और 4जी सेवाओं के लिए 700 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम को सबसे माकूल माना जाता है लेकिन इसके लिए बोली न आने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्तरीय डेटा सेवाओं के प्रसार पर विपरीत असर देखने को मिलेगा। तीव्र, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली डेटा सेवा अर्थव्यवस्था में नई जान डाल सकती है। *डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसे अभियानों की कामयाबी के लिए भी यह जरूरी है।* ऐसे में अनबिके स्पेक्ट्रम के आरक्षित मूल्य को कम रखने और नए सिरे से नीलामी किए जाने की आवश्यकता है। संचार मंत्री मनोज सिन्हा का इस तरह का संकेत देना स्वागतयोग्य कदम है।

Prepare IAS
Current Affairs (Oct.7 to Oct.14)
From plate to plough-Rural change challenge

Indian Express

Eradicating poverty from the planet was the top-most target in a set of 17 goals adopted by the UN last September as a part of its sustainable development agenda. Nations across the globe, including India, endorsed it. The strategies to achieve this goal have been left open to countries. In this context, the Rural Development Report (RDR) 2016 of the International Fund for Agricultural Development is timely.

G.S. Paper III: Indian economy

** Inclusive agricultural growth is key to removing poverty by 2030.

The RDR's Asia and Pacific Region (APR) release will be in India on October 17. The report is among the more comprehensive documents that try to understand the role of rural transformation in eradicating poverty and securing food and nutritional security within the context of economy-wide structural transformation in several countries. It is based on an empirical analysis of 60 countries drawn from various regions. Nine are from the APR. Comprising Bangladesh, Cambodia, China, India, Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Pakistan, Philippines and Vietnam, the region is the most populous and has the largest number of poor on this planet. There are 16 countries from Latin America and the Caribbean; seven from the Near East, North Africa, Europe and Central Asia; 15 from East and Southern Africa; and 13 from West and Central Africa.

RDR 2016's first lesson pertains to the conceptual framework of development. It notes that economies of almost all the 60 countries are undergoing some sort of structural transformation — some are moving fast, many are moving at a moderate pace and some are going very slow. The transformation is reflected in rising productivities in agriculture and the urban economy as well as in the changing character of the economy — the preponderance of agriculture making way for the dominance of industry and services, greater integration with global trade and investments and growing urbanisation.

RDR's second lesson is that rural areas cannot remain insulated from this economy-wide change. They are also transformed with rising agricultural productivity, increasing commercialisation and marketable surpluses, diversification to high-value agriculture and off-farm employment through the development of agri-value chains. **The third, and the most important lesson, especially for policymakers, is that rural transformation on its own may not be effective in reducing poverty unless it is inclusive.** This challenge is at the heart of the report. Agricultural development is a key element of such inclusiveness since a majority of the working force in most countries at low to moderate levels of rural transformation is still engaged in agriculture.

What can India learn from this, given that agriculture still engages half of its workforce, and about 85 per cent of its farms are small and marginal (less than two hectares)? Compared to China and Vietnam, which have experienced fast structural and rural transformation, India's story is of slow transformation. As a result, poverty reduction in India was at a much slower pace during 1988-2014, compared to China and Vietnam. The RDR 2016 tells us that India's poverty reduction was slow

during 1988-2005, but during 2005-12, it accelerated dramatically — almost three times faster than during the earlier period.

What did India do during this period? Research reveals that the relative price scenario changed significantly (by more than 50 per cent) in favour of agriculture in the wake of rising global prices. This boosted private investments in agriculture by more than 50 per cent. As a result, agri-GDP growth touched 4.1per cent during 2007-12, as against 2.4 per cent during 2002-07. The net surplus of agri-trade touched $25 billion in 2013-14; real farm wages rose by seven per cent per annum. All these led to an unprecedented fall in poverty. A good price incentive can thus trigger investments in agriculture, leading to productivity gains, increases in real farm wages and fall in poverty.

To make the rural transformation more inclusive, India will have to focus on raising productivity in agriculture through higher R&D (seeds) and irrigation and build value chains for high value agri-products like livestock and horticulture, which account for more than half the value of agriculture (cereals account for less than 20 per cent). In the building of these value chains by mainstream small holders — say, through farmer producer companies — India can create large off-farm rural employment and augment incomes of farmers and others living in rural areas. This would require large investments both by the private and public sector. If India can do all this efficiently and through a participatory mode, it can certainly hope to eliminate not only poverty but also malnutrition by 2030. For more details on RDR 2016, stay tuned till October 17.

SC widens ambit of Domestic Violence Act The Hindu

In a landmark verdict, the Supreme Court has widened the scope of the Domestic Violence Act by ordering deletion of the words "adult male" from it, paving the way for prosecution of women and even non-adults for subjecting a woman relative to violence and harassment.

***G.S.Paper II: Polity &* Govt policies & interventions for development in various sectors & issues arising out of their design & implementation**

The top court has ordered striking down of the two words from section 2(q) of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, which deals with respondents who can be sued and prosecuted under the Act for harassing a married woman in her matrimonial home.

Referring to earlier verdicts, the top court said "*the microscopic difference between male and female, adult and non adult, regard being had to the object sought to be achieved by the 2005 Act, is neither real or substantial, nor does it have any rational relation to the object of the legislation."*

Section 2(q) of the Act reads: "'respondent' means any adult male person who is, or has been, in a domestic relationship with the aggrieved person and against whom the aggrieved person has sought any relief under DV Act."

A bench of Justices Kurian Joseph and R F Nariman paved way for prosecution of any person irrespective of gender or age under the Domestic Violence Act, ordered deletion of the words "adult male" from the statute book saying it violated right to equality under the constitution.

The bench said that the words "adult male person" were contrary to the object of affording protection to women who have suffered from domestic violence "of any kind".

"We, therefore, strike down the words 'adult male' before the word 'person' in Section 2(q), as these words discriminate between persons similarly situated, and far from being in tune with, are contrary to the object sought to be achieved by the 2005 Act," it said.

The major verdict came on an appeal against the Bombay High Court judgement, which had resorted to the literal construction of the term 'adult male' and discharged four persons, including two girls, a woman and a minor boy, of a family from a domestic violence case on the ground that they were not "adult male" and hence cannot be prosecuted under the Domestic Violence Act.

GS – III: Issue related to Environment

The Montreal Protocol, which came into force in 1989, is aimed at reducing the production and consumption of ozone depleting substances in order to protect the earth's fragile ozone layer. Even with the complete phase-out of HCFCs; for usage as refrigerants under the Montreal Protocol, its production will continue for feedstock purposes.

INDIA TO ELIMINATE USE OF HFC-23 BY 2030 HTmint

At a meeting of parties to the Montreal Protocol at Kigali in Rwanda where final negotiations are taking place substantially reduce the use of HFCs (Hydrofluorocarbons) by 2030,India said it would eliminate the use of HFC-23, a greenhouse gas that harms the ozone layer, by 2030.

The move will potentially check emissions of HFC-23 equivalent to 100 million tonnes of CO2 over the next 15 years. Also, India is sending a strong signal to the world that it is serious about the climate change issue. This move will have a positive impact on the discussions on HFCs and will make the governments and producers of HCFC-22 in both developed and developing countries think on emulating this practice.

About HFC-23:

HFC-23, a potent greenhouse gas with global warming potential of 14,800 times more than that of CO2, is a by-product of HCFC-22, which is used in industrial refrigeration.

MALDIVES QUITS COMMONWEALTH

The Maldives on Thursday pulled out of the Commonwealth calling the grouping's decision to penalise the island nation over the circumstances as unjust that led to then President Mohamed Nasheed's ouster in 2012 and the lack of subsequent progress in resolving the political unrest. The Commonwealth Ministerial Action Group (CMAG) had warned Maldives of suspension from the bloc over the country's lack of progress in resolving the political crisis. The Maldives said that in the name of promotion of democracy, the grouping used the country to increase the organization's own relevance and leverage in international politics.

The Commonwealth has sought to take punitive actions against the Maldives since 2012 after the then President of Maldives resigned.

GS-II: Issues related to International Relation

**** The Commonwealth, or The Commonwealth of Nations, is a group of 53 states, all of which (except for two) were formerly part of the British Empire. As nations began the process of succeeding from the British Empire in the early part of the 1900s, it was created, largely, to ease the process of British decolonization.**

मालदीव ने राष्ट्रमंडल छोड़ा

मालदीव ने स्वयं को राष्ट्रमंडल से अलग करते हुए 2012 में राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को सत्ता से हटाए जाने की परिस्थितियों पर और उसके बाद राजनीतिक संकट सुलझाने की दिशा में प्रगति नहीं होने पर द्वीप राष्ट्र को सजा देने के समूह के फैसले को 'अन्यायपूर्ण' बताया। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रमंडल छोड़ने के इस फैसले को 'मुश्किल' और 'अपरिहार्य' बताया। राष्ट्रमंडल 53 देशों का समूह है, जिसके ज्यादातर सदस्य ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व उपनिवेश हैं। पिछले महीने राष्ट्रमंडल मंत्रिस्तरीय कार्रवाई समूह (सीएमएजी) ने राजनीतिक संकट सुलझाने की दिशा में प्रगति नहीं होने पर 'गहरी निराशा' जताते हुए मालदीव को संगठन से निलंबित करने की चेतावनी दी थी।

राष्ट्रमंडल के लिए बेहद महत्वपूर्ण मालदीव ने कहा कि लोकतंत्र को बढ़ावा देने के नाम पर समूह ने देश का उपयोग सिर्फ संगठन की प्रासंगिकता और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में लाभ को बढ़ाने के लिए किया। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, '2012 में मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति (नशीद) के इस्तीफा देने और संविधान में तय प्रक्रिया के तहत सत्ता का हस्तांतरण होने के बाद से ही राष्ट्रमंडल मालदीव के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग कर रहा है।' बयान के अनुसार, 'मालदीव को दंड देने का राष्ट्रमंडल का फैसला अन्यायपूर्ण है, विशेष रूप से तब जब राष्ट्रमंडल की मदद से गठित राष्ट्रीय जांच आयोग (सीओएनआई) ने पाया कि मालदीव में सत्ता का हस्तांतरण संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हुआ है।'

मालदीव ने कहा कि तभी से सीएमएजी और राष्ट्रमंडल सचिवालय ने मालदीव के साथ 'अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण' व्यवहार किया है। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'राष्ट्रमंडल ने मालदीव के घरेलू राजनीतिक मामलों में सक्रिय भागीदार बनने की बात कही, जो संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रमंडल के चार्टर के सिद्धांतों के खिलाफ है।' उसमें कहा गया है, 'मालदीव आश्वासन देता है कि उसके अंतरराष्ट्रीय संबंध.. द्विपक्षीय और बहुपक्षीय.. दोनों बने रहेंगे।' मालदीव ने कहा कि वह बड़ी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ 1982 में राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ था और उसे लगा था कि यह मंच सदस्य देशों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर समन्वय करेगा, विशेष रूप से संगठन में शामिल छोटे राष्ट्रों के साथ।

सीएमएजी ने 2012 में राष्ट्रपति नशीद को सत्ता से हटाए जाने संबंधी जांच के लिए गठित आयोग की आलोचना की है। बयान में कहा गया है, '2012 से ही मालदीव की सरकार राष्ट्रमंडल के साथ सबसे ज्यादा सहयोग कर रही है, पारदर्शिता दिखायी और उच्चतम स्तर पर राष्ट्रमंडल के साथ जुड़ी रही है।' उसमें कहा गया है, 'राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम की सरकार ने कुल 110 कानून लागू किए हैं। उनमें से 94 राष्ट्रमंडल के चार्टर के मूल सिद्धांतों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं।'

Prepare IAS
Current Affairs (Oct.7 to Oct.14)

Prelims Points:-

1- **October 10: World Mental Health Day** - The World Mental Health Day (WMHD) is observed every year on 10 October to raise awareness about mental health issues around the world and mobilizing efforts in support of mental health. **Theme for 2016 : "Psychological First Aid".** It was first celebrated in 1992.

2- **October 9: World Post Day** The World Post Day is observed each year on October 9 to spread awareness about the postal services and their role in the everyday lives of people and businesses. **Theme for 2016 : "Innovation, Integration and Inclusion".** *The day is celebrated to mark anniversary of the establishment of the Universal Postal Union (UPU) in 1874 in the Swiss Capital, Bern.*

3- **October 11: International Day of the Girl Child** The International Day of the Girl Child (IDGC) is observed every year across the world on 11 October to recognize girls' rights and the unique challenges girls face around the world. Theme for 2016 : "Girls' Progress = Goals' Progress: What Counts for Girls".

4- 4th BRICS Science, Technology and Innovation Ministerial Meeting held at Jaipur October 11, 2016. The purpose of the meeting was to further strengthen the collaboration amongst the BRICS countries in the areas of Science, Technology and Innovation (STI). Key Facts The meeting adopted a five-pronged approach, viz. Institution Building, Implementation, Integration, Innovation and Continuity.

5- **October 13: International Day for Disaster Reduction** The International Day for Disaster Reduction (IDDR) is observed annually on 13 October across the world encourage citizens and governments to take part in building more disaster resilient communities and nations. Theme for 2016 : "Live to Tell: Raising Awareness, Reducing Mortality".

6- विश्व मानक दिवस: 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है. वर्ष 2016 के लिए विश्व मानक दिवस की थीम है - "मानक विश्वास निर्मित करते हैं". अंतरराष्ट्रीय मानक, ऊर्जा उपयोगिताओं और परिवहन के लिए ऊर्जा दक्षता, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य से लेकर विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञों में सर्वसम्मत विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं.

7- सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले थाईलैंड नरेश का निधन विश्व में सबसे लम्बे समय तक शासन सँभालने वाले, थाइलैंड के **नरेश भूमिबल अदुल्यदेज** का लंबी बीमारी के बाद 88 वर्ष की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया. राजा भूमिबल, 234 वर्ष पुराने **चक्री वंश के 9वें** राजा थे. उनके निधन के बाद अब 63 वर्षीय राजकुमार महा वाजिरालोंगकोर्न गद्दी संभालेंगे.

8- **पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जायेगा** भारत सरकार पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनायेगी. यह आगामी समय में होने वाली, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (AMCDRR) 2016 के दौरान मनाया जायेगा. 2-5 नवंबर तक यह सम्मलेन दिल्ली में होने की उम्मीद है.

9- देवेंद्र फडणवीस द्वारा भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने शनिवार को मुंबई में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया. मुंबई अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (MCIA) प्रारंभ में एक्सप्रेस टावर में स्थित होगा. MCIA 17-सदस्सीय संचालन परिषद् द्वारा संचालित किया जाएगा.

10- बठुकम्मा उत्सव गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकाड्र्स में दर्ज तेलंगाना सरकार ने शनिवार को हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में राज्य के पारंपरिक उत्सव "बठुकम्मा" का आयोजन किया. इस उत्सव में दस हजार महिलाओं ने भाग लिया और इसलिए इसे गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकाड्र्स में स्थान दिया गया. तेलंगाना सरकार ने "बठुकम्मा" उत्सव को अपना राज्य उत्सव घोषित किया है.